आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)
सोमवार 23.03.2026
समय 0720

मुख्य समाचार :–

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति के मद्देनजर कच्चे तेल और गैस की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
- केंद्र सरकार ने फिर कहा कि देश भर में आवश्यक ईंधन की कोई कमी नहीं।
- प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर देहरादून में आज 'जन–जन की सरकार, चार साल बेमिसाल' कार्यक्रम का आयोजन।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल के नवनियुक्त सदस्यों को विभागों का दायित्व सौंपा।
- और... मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जिलों में बारिश की संभावना जताई है।

उच्च स्तरीय बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति के मद्देनजर पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य निर्बाध आपूर्ति, स्थिर रसद और देश भर में कुशल वितरण सुनिश्चित करना था। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर सहित कई केंद्रीय मंत्री और अधिकारी उपस्थित रहे।

ईंधन

केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश भर में आवश्यक ईंधन की कोई कमी नहीं है, तेल शोधन संयंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त भंडार है। खुदरा दुकानों पर भी किसी प्रकार की कमी की सूचना नहीं है।

सरकार ने देशभर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की स्थिर उपलब्धता सुरक्षित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है और घबराहट में की जाने वाली बुकिंग कम हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाई गई है। इसमें स्कूलों और अस्पतालों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन बढाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए देशभर में छापेमारी की जा रही है। वहीं, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि वह समुद्री व्यापार को जारी रखने के लिए जहाजों की आवाजाही, बंदरगाह संचालन और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर नजर रख रहा है।

जन जन की सरकार

प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 'जन–जन की सरकार, चार साल बेमिसाल' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से सरकार की विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। देहरादून में मुख्य समारोह को देखते हुए पुलिस ने यातायात योजना लागू की है, ताकि आवागमन सुचारू रूप से बना रहे।

चार साल बेमिसाल

राज्य में भाजपा सरकार के चार साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षों में आमजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

आकाशवाणी समाचार देहरादून, सरकार की चार साल की उपलब्धियों पर एक विशेष श्रृंखला– 'चार साल बेमिसाल' प्रस्तुत कर रहा है। आज की कड़ी में राज्य आंदोलनकारियों, सैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं और आम नागरिकों के लिए चलाई गई प्रमुख योजनाओं पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट–

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अपने चार वर्ष के कार्यकाल में राज्य आंदोलनकारियों, सैनिकों और आमजन के सम्मान तथा कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य आंदोलनकारियों के योगदान को सम्मान देते हुए सरकारी नौकरियों में उन्हें 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही, उनके आश्रितों की पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। इसके अलावा, राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन तक जेल में रहे अथवा घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 6000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। सैनिकों ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, परमवीर चक्र विजेताओं के लिए यह राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दी गई है। अग्निवीर योजना के अंतर्गत सेवा देने वाले युवाओं को भी सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी है। अब बुजुर्ग दंपति में दोनों को ही इसका लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों और लेखकों की मासिक पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। पिछले चार वर्षों में लिए गए इन फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने न केवल विकास को गति दी है, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है।

मंत्रिमंडल विस्तार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल के नवनियुक्त सदस्यों को विभागों का दायित्व सौंप दिया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की ओर से जारी अधिसूचना में बताया कि मुख्यमंत्री ने वित्त, गृह, राजस्व, औद्योगिक विकास, ऊर्जा, आवास, पेयजल सहित 18 महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं, कैबिनेट मंत्री खजान दास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण और भाषा विभाग दिए गए हैं, जबकि कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी को ग्राम्य विकास और ग्रामोद्योग विभाग सौंपे गए हैं।

वहीं, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को पंचायतीराज, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, आयुष एवं आयुष शिक्षा, और जनगणना विभाग दिए गए हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा को परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व जैव प्रौद्योगिकी विभाग आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा को शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन औए जलागम प्रबंधन विभाग सौंपे गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेलों की स्थिति से संबंधित ताजा आंकड़े 18 मई तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें कैदियों की स्वीकृत क्षमता और भीड़भाड़ से निपटने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने हाल में एक आदेश में महिला जेलों की संख्या और उपलब्ध सुविधाओं का विवरण भी मांगा है, जिसमें महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों की शिक्षा और कल्याण के उपाय भी शामिल हैं।

ग्रीन कार्ड

परिवहन विभाग ने आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नए नियमों के तहत यात्रा में शामिल होने वाले "केयर ऑफ" में पंजीकृत वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने से पहले विशेष सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा।

एआरटीओ निखिल शर्मा के अनुसार, स्थानीय ट्रेवल कारोबारियों की मांग पर "केयर ऑफ" में वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक सख्त बनाया गया है, ताकि केवल वैध और मानकों पर खरे उतरने वाले वाहन ही यात्रा में शामिल हो सकें।

मौसम

मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस अवधि में आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान है। साथ ही तीन हजार से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अनुमान है।

वहीं मैदानी जिलों मौसम शुष्क बना रहेगा।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर....

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ईरान को 48 घंटे में होर्मुज खोलने की चेतावनी को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। इस खबर पर दैनिक जागरण का शीर्षक है– होर्मुज खोलो वरना करेंगे बत्ती गुल।

आंध्र प्रदेश में मिलावटी दूध पीने से 16 की मौत– शीर्षक के साथ हिन्दुस्तान लिखता है– राज्य सरकार ने कहा – दूध एथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीले पदार्थ से दूषित था।

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल पर नवोदय टाइम्स की सुर्खी है– सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड

प्रदेश कैबिनेट विस्तार पर अमर उजाला लिखता है– पांच नए मंत्रियों को दी जिम्मेदारी, पुराने चार मंत्रियों के विभागों में किया फेरबदल